

(ख) उक्त राज्य सरकार इस दिशा में कहां तक सफल हुई है ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निर्धनता रेखा के ऊपर उठाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम बुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राज्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संसद कक्ष में कर्मचारियों को समयो-
परि भत्ता

4255. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के संसद कक्षों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्टाफ कार ड्राइवरों की तुलना में काफी देर तक कार्य करना पड़ता है लेकिन उन को स्टाफ कार ड्राइवरों की तुलना में समयो-परि भत्ते की अदायगी कम की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में फिर से विचार करने और कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक समान समयोपरि भत्ते की अदायगी करने के आदेश जारी करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुबबैया) : (क) स्टाफ कार ड्राइवरों को समयोपरि भत्ते की अदायगी स्टाफ कार नियमों द्वारा विनियमित की जाती है, जब

कि संसद एककों में कार्यरत कर्मचारियों सहित सभी अन्य कार्यालय कर्मचारियों तथा इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ता अलग प्रादेशों से शासित होता है । स्टाफ कार ड्राइवरों के कार्य का स्वरूप तथा उनके कार्य के घंटे अन्य कार्यालय कर्मचारियों तथा इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों से भिन्न होते हैं । अतः समयो-परि भत्ते के भुगतान के संबंध में कर्मचारियों के इन दो प्रवर्गों की तुलना करना उपयुक्त नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Death Sentence

4256. SHRI LAKSHMAN MALLICK:
Will the Minister of HOME AFFAIRS
be pleased to state :

(a) the number of death sentences commuted by the President during the last three years; and the guidelines for commuting the death sentences;

(b) the number of death sentences, during the last three years, state-wise and years-wise, confirmed after the appeal rejected by the Supreme Court; and

(c) whether Government have received any comments from the public or expert lawyers regarding its abolition ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a)
and (b) The power of the President
under article 72 of the Constitution
to commute a sentence of death is abso-
lute and unfettered and a decision is
taken by the President on the merits of
each prisoner's case. During the three
year period ending with 14th August, 1984
the President was pleased to commute the
death sentences of five condemned pri-
soners. A statement indicating the num-

ber of prisoners. Statewise and year-wise, who were executed or are awaiting execution after their mercy petitions were rejected by the President during the same period after rejection of their appeals by the Supreme Court is attached:

(c) No comments from the public or expert lawyers were received after the Supreme Court in Bachan Singh and others Vs. State of Punjab (AIR 1980 Supreme Court 898) had upheld the validity of the death penalty.

Statement

State/Union Territory		Number of Prisoners who were executed or the awaiting execution after rejection of their Mercy Petition during the year ending.	
1	2	3	4
	14.8.82	14.8.83	14.8.84
Bihar	...	2	...
Gujarat	...	1	...
Haryana	...	2	...
Jammu & Kashmir	1
Karnataka	...	1	...
Madhya Pradesh	...	2	...
Maharashtra	1	6	1
Punjab	...	5	4
Rajasthan	...	1	...
Tamil Nadu	...	6	1
Uttar Pradesh	...	3	1
Delhi	2	2	...
Total	3	31	8

Reservation for SC/ST in Visakhapatnam Steel Plant

4257. SHRI JAGPAL SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 998 on 9 May, 1984 regarding filling up of executive posts

reserved for SC/ST in Visakhapatnam Steel Plant and state :

(a) existing promotion policy for non-executives employees ;

(b) number of non-executives (cadre-wise and post-wise) promoted since 1st